Vol-1, Issue-2 60

डिजिटल अर्थव्यवस्था (भारत के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राजेश मौर्य

सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग

शासकीय नेहरू महाविद्यालय. सबलगढ, मुरैना

प्रो. जे. पी. मित्तल

प्राचार्य

शासकीय नेहरू महाविद्यालय. सबलगढ, मुरैना

शोध-सारः

सामान्य शब्दों में डिजिटलीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत एक इलैक्ट्रोनिक्स पद्धति के माध्यम से 0 से लेकर 1 तक की संख्याओं या सूचनाओं को भेजने का कार्य किया जाता है। यह एक सरल व आसान प्रक्रिया है, जो लोगों के कार्यों को तीव्रगति से कम से कम समय में पूर्ण करने की क्षमता रखती है। विश्व में इस प्रक्रिया को तब पहचाना गया था, जब सन 1995 में डॉन टेपसस्कॉंट की प्रसिद्ध पुस्तक- द डिजिटल इकोनॉमी- प्रोमिस एण्ड पेरिल इन द ऐज ऑफ नेटवर्क इंटेलिजेस में इस शब्द को पढ़ा गया था। इसके बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक क्रांति का उदभव हुआ और विश्व के अधिकाँश देशों ने इसे अपनाना प्रारंभ किया था। भारत के संदर्भ में इस अर्थव्यवस्था की शरूआत सन 1990-91 के दशक में आर्थिक सधार कार्यक्रम के परिणामस्वरूप हयी थी, जिसके तहत सर्वप्रथम बैकिंग क्षेत्र में ए.टी.एम. (ATM) मशीनों के माध्यम से लोगों की नगद लेनदेन प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ था। इस अवधारणा ने न केवल लोगों के व्यवहार व बातचीत की पद्धति में बदलाव उत्पन्न किया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरणों के उपयोग में वृद्धि हुयी थी और समय के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था नवीन उत्पादों, तकनीकी, डिजिटल उत्पादों व सेवाओं पर केन्द्रित हो गयी थी। आज भारतीय अर्थव्यवस्था ने डिजिटल क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति हासिल कर ली है कि विश्व के चीन तथा संयक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बडी डिजिटल अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में न केवल निजी कंपंनियों व व्यवसायों का योगदान रहा है, बल्कि भारत सरकार ने भी अपना भरपर सहयोग दिया है। वर्ष 2015 में आरंभ किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इसका प्रमाण है, जिसके तहत हमने विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम आयोजित करके देश के लगभग सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। डिजिटल पहचान कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल 1.2 बिलियन से अधिक भारतीयों को जोड़ा जा चका है. जबकि निजी क्षेत्र में रिलायंस तथा इन्टरनेट का सर्च इंजन गगल (Google) है. जिन्होंने इन्टरनेट के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न कररके अधिक से अधिक लोगों को इन्टरनेट का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया है। वर्ष 2018 के ऑंकडे बताते है कि लगभग 560 मिलियन भारतीय लोगों ने इन्टरनेट का उपयोग किया था। इन सभी आँकडों के आधार पर कहा जा सकता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत का भविष्य अति उत्तम है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल रूप से विश्व की सबसे बडी अर्थव्यवस्था होगी।

बीज शब्द :

मोबाईल फोन, इन्टरनेट, सोशल मीडिया के उपकरण, डिजिटल पहचान कार्यक्रम

अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक स्रोतों से यह पता चलता है कि सम्पूर्ण दुनिया में भिन्न-भिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जैसे:- समाजवादी, साम्यवादी, पूँजीवादी, मिश्रित आदि संचालित रही है, जिनका अध्ययन हमने अर्थशास्त्र जैसे विषय के अन्तर्गत किया है, लेकिन जैसे-जैसे मानव विकास या प्रगति के पथ पर अग्रसर होता गया, वैसे-वैसे नयी-नयी विचारधाराएं, सभ्यताएं तथा देशों की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन होता गया और इसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक नयी अर्थव्यवस्था का प्रार्दुभाव हुआ, जिसे डिजिटल या वेब या मंच अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है।

पूर्वोत्तर प्रभा वर्ष-1, अंक-2 जुलाई-दिसंबर 2021

21वीं सदी में संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसमें कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के सहयोग से इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। इन्टरनेट के सर्वाधिक इस्तेमाल के कारण ही इसे वल्ड वाईब वेब या इन्टरनेट अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसमें सभी प्रकार की व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक एवं साँस्कृतिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। आज कल जैसे-जैसे सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एकीकृत होकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है, वैसे-वैसे आर्थिक एवं वाणिज्य लेनदेन और आधुनिक तकनीकी युक्त पेशेवर (लोगों) का व्यवहार या बातचीत का तरीका एक डिजिटल युक्त विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है।

विश्व में पहली बार डिजिटल अर्थव्यवस्था को उस समय पहचाना गया था, जब सन 1995 में डॉन टेपस्कॉट की प्रसिद्ध पुस्तक - "द डिजिटल इकॉनोमी- प्रोमिस एण्ड पेरिल इन द ऐज ऑफ नेटवर्क इंटेलिजेस" में इस शब्द को पढ़ा गया था। इसके बाद यह सम्पूर्ण विश्व में अपने-अपने देशों की आर्थिक विकास दर को शीर्ष पर पहुँचाने के लिये उपयोग किया जाने लगा था, क्योंकि वर्तमान में न केवल लोग बल्कि देश की अर्थव्यवस्थाएं भी डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गयी है।

डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के क्षेत्र में न केवल विकसित देश शामिल है, बल्कि कई विकासशील देशों ने भी स्वीकार किया है। इसी विकासशील देशों की श्रृंखला में हमारा देश भारत भी शामिल है, जिसने भारत के संदर्भ में डिजिटल अर्थव्यवस्था को सन 1990 के दशक से अपनाया था।2 तब से यह (देश) बदलती हुयी प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अपने देश के आर्थिक विकास हेत् विभिन्न व्यावसायिक संगठनों एवं वाणिज्य क्षेत्रों में सतत रूप से उपयोग किये जा रहा है। हाल के वर्षो में इसमें (डिजिटल अर्थव्यवस्था) कुछ परिवर्तन हुये हैं अर्थात यह डिजिटल अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रौद्योगिकी, तकनीकी, नवीन उत्पादों एवं सेवाओं पर केन्द्रित हो गयी है और भारत ने भी इसे स्वीकार किया है तथा इस क्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। आँकड़े बताते हैं कि किस प्रकार भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2021 की चैथी तिमाई में 82.5 मिलियन भारतीय उपभोक्ता इन्टरनेट के क्षेत्र में अग्रणी है।³ इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण दुनिया में भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने के क्षेत्र में सर्वाधिक अग्रणी है।

अध्ययन के उद्देश्यः- डिजिटल अर्थव्यवस्था (भारत के संदर्भ में) नामक शोध पत्र के लिये निम्नलिखित उद्देश्यों का चयन किया गया है।

1-डिजिटल अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझना।

2-भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझना। 3-भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य को समझना।

अध्ययन की सामग्री:- यह शोध पत्र पूर्णरूप से द्वितीयक समंको पर आधारित है। इसे पूर्ण करने के लिये मैने विभिन्न समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध जर्नलों, पुस्तकों तथा इन्टरनेट पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों से सम्पर्क एकत्रित करके किया है।

उपलब्ध साहित्य का अध्ययनः- किसी भी विषय क्षेत्र में शोध कार्य आरंभ करने से पूर्व उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल शोधकर्ता के शोध को आकार, निर्दशन प्रणाली का चयन, परिकल्पनाओं का निर्माण तथा साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करता है, बल्कि उसे (शोधकर्ता) अपने शोध क्षेत्र में भटकने से भी राहत प्रदान करता है, इसीलिये उपलब्ध साहित्य का अध्ययन महत्वपूर्ण है।

मोइंक मैती और पार्थजीत कायल (2017) ने अपने लेख - "डिजिटाइजेशनः- आर्थिक विकास तथा व्यापार पर उसका प्रभाव" में उल्लेख किया है कि किसी भी देश में डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया आई. टी (IT) तथा आई. टी. ई. एस (ITES) जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय विकास की पद्धित को स्वचालित एवं संशोधित करती है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सम्पूर्ण उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र में समग्र सुधार हुआ। इसी कारण भारत के सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से भविष्य में उच्च विकास की संभावनायें उत्पन्न हुयी है।"4

साईमा खान, डॉ. साईना और अफताब मोहसिना (2015) ने अपने लेख - "डिजिटलाईजेशन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव" में यह प्रस्तुत किया है कि पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल रूपांतरण की दृष्टि से तेजी से सुधार हुआ है। यह रूपांतरण डिजिटल जानकारी को साझा एवं संसाधित करने तथा प्रबोधित करने हेतु बड़े पैमाने पर उपयोग करने से आरंभ हुआ है। इस प्रकार डिजिटलीकरण की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन, रूपांतरण संरक्षण तथा पहुँच की एक व्यापक तकनीक है, जिसके द्वारा व्यावसायिक संगठनों की समस्त सम्पत्तियों को डिजिटल रूप से पुनः तैयार किया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल तकनीक को अपनाया जाता है।"5

डॉ. मानसी शुक्ला तथा शिल्पी बोस (2017) ने अपने डिजिटल अर्थव्यवस्था संबंधी लेख - "अर्थव्यवस्था तथा विमुद्रीकरण पर डिजिटलाईजेशन का प्रभाव" में उल्लेख किया है कि किसी भी वस्तु एवं सेवा के विक्रय के संबंध में डिजिटलीकरण का मतलब क्रेता एवं विक्रेता के बीच केवल आमने-सामने से ऑनलाईन कारोबार करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह (डिजिटलीकरण) व्यापार से संबंधित अनेक पक्षो या पहलुओं में परिवर्तन करने से भी

संबंधित है। डिजिटलीकरण व्यापार के क्षेत्र में नवाचारों को स्वीकार करते हुए लोगों (उद्योगपितयों, क्रेता, विक्रेता, निवेशक) के व्यवहारों एवं बातचीत करने के तरीकों को प्रभावित करता है और औद्योगिक तथा वाणिज्य गतिविधियों के विकास में तेजी से सुधार कर शीर्ष पर पहुँचाने का कार्य करता है।"6

उपरोक्त उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि डिजिटलाईजेशन से संबंधित साहित्य में अर्थव्यवस्था, व्यापार व व्यवसाय को प्रभावित करने वाले विशेष पहलू और विशेष व्यक्तियों जैसे- क्रेता, विक्रेता तथा उद्योगपितयों के व्यवहार आदि पर जोर दिया गया है। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य कैसा है \ आदि पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, इसलिये मैंने अपने शोध पत्र में इन कारकों पर दृष्टि डाली है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है:- सामान्य शब्दों में डिजिटल अर्थव्यवस्था वह है, जिसके अन्तर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों का संचालन नवीनतम तकनीक अर्थात सूचना व संचार प्रौद्योगिक से संबंधित उपकरणों (कम्प्यूटर, इन्टरनेट) के माध्यम से किया जाता है। यदि हम इसे यह कहें कि यह अर्थव्यवस्था इन्टरनेट या वेब प्रौद्योगिकी के आधार पर संचालित होती है, तो इसमें कोई आतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के ये सभी उपकरण इन्टरनेट के द्वारा ही संचालित होते हैं। यही कारण है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को वेब इकोनोमी या इंटरनेट इकोनोमी के नाम से भी जाना जाता है।

प्रारंभिक अवस्था में डिजिटल अर्थव्यवस्था को वेब या इंटरनेट अर्थव्यवस्था कहा जाता था, जो कि उचित नहीं है अर्थात अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सटीक प्रतीत नहीं होती है। अर्थशास्त्रियों एवं पेशेवर लोगों (व्यापार विशेषज्ञ, निवेशक, उद्योगपित) का कहना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था इन्टरनेट अर्थव्यवस्था की तुलना में कही अधिक जटिल व उन्नत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अनेक घटक या चरण (आय, रोजगार, उपभोग, उत्पादन, निवेश, व्यापार व व्यवसाय) है, जिन्हें एक साथ एक ही समय पर इन्टरनेट के माध्यम से संचालित करना संभव नहीं है, इसीलिये डिजिटल अर्थव्यवस्था जटिल है।

परिभाषाएँ-

विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों तथा सामाजिक-आर्थिक, दार्शनिकों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया है।

मेरी के प्रात (Mery k. pratt) के अनुसार - "आर्थिक दृष्टि से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधियों, वित्तीय संबंधी लेनदेनों और पेशेवरों के बीच बातचीत एवं व्यवहार का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है,

जिसका संचालन संचार व सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है।"⁷

रमीजा बी (Ramija, B, 2018) के अनुसार - ''डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जो पारम्परिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है और डिजिटल कम्प्युटिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित है, चूँिक इसके अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर इन्टरनेट का उपयोग किया जाता है, इसीिलये इसे इन्टरनेट या वेब अर्थव्यवस्था कहा जाता है।''8

बेयरफुट बी (Barefoot, B, 2018) के अनुसार - "जब से अर्थात 1990 के दशक से डिजिटल अर्थव्यवस्था का स्वरूप उभरकर आया, वैसे ही डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिभाषा विकसित हुयी, जो प्रौद्योगिकी को तेजी से परिवर्तित स्थिति या प्रकृति, उद्यमों तथा उपभोक्ताओं द्वारा इसके उपयोग को दर्शाती है।"

ब्रेयनजोल्फसन तथा कहीन (Brynjolfsson and Kahin, 2002) के अनुसार - "डिजिटल अर्थव्यवस्था इन्टरनेट को अपनाने तथा इसके प्रारंभिक आर्थिक प्रभावों के बारे में सोच से संबंधित है।"¹⁰

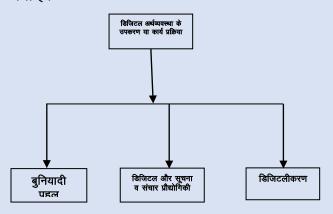
डी. एस. ईवांस (D. S. Evans, 2003) ने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिभाषा के अन्तर्गत इसे प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था कहा है, उनके अनुसार - "पारम्परिक बाजार अर्थव्यवस्था में विशिष्ट रूप से दो तरफा बाजारों की अनूठी आर्थिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में इसे (डिजिटल अर्थव्यवस्था) परिभाषित करते हैं।"11

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन "विश्व बैंक" ने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था संबंधी परिभाषा के अन्तर्गत विकासशील देशों द्वारा अपनायी जा रही डिजिटल अर्थव्यवस्था को शामिल करते हुए कहा है कि - "आज जिस प्रकार से इन देशों में इसे स्वीकार किया जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ या इन देशों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की बेहत्तर सुविधाओं के साथ-साथ उत्पादों तथा सेवाओं की श्रेणी में सुधार हुआ है और तेजी से इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है।"12

एस ब्रेनन और कृर्सि डी (S. Brennen and Kreiss. D 2014) उन्होंने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था संबंधी परिभाषा के अन्तर्गत डिजिटल प्रौद्योगिकियों, तकनीक, उत्पाद व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि - "पिछले कुछ वर्षों में देशों की अर्थव्यवस्थों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं (उत्पाद व सेवायें), तकनीकी व इससे संबंधित कौशल का जिस गति से प्रसार हुआ है, उसकी वजह से यह डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तित हो गयी है। यही कारण है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेवाओं व उत्पादों के माध्यम से संचालित किये जा रहे विभिन्न उद्योगों व व्यवसायों के रूप में इसे परिभाषित किया जा रहा है।"¹³

डिजिटल अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से समझने के लिये इसकी परिभाषाओं के साथ-साथ इसके उपकरण या घटकों को भी समझना महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह पता चलेगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के कौन-कौन से उपकरण है तथा यह कैसे काम करते हैं।

ii. डिजिटल अर्थव्यवस्था के उपकरण या कार्य प्रक्रियाः-इसके अन्तर्गत डिजिटल अर्थव्यवस्था के यंत्रों या कार्य प्रक्रिया के तहत इसे तीन भागों (घटकों) में विभाजित किया गया है।



a) बुनियादी पहलू:- किसी भी क्षेत्र या विषय या उत्पाद के संबंध में बुनियादी पहलू का मतलब एक आधार या वह जिस पर खड़ा है या बना है, से होता है। यह उसी प्रकार से होता है, जिस तरह एक मकान उसकी नींव के खम्बों पर खड़ा होता है। इस दृष्टि से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बुनियादी पहलुओं से भौतिक (नवाचार), दूरसंचार उपकरण, कम्प्यूटर और वह कमरा या कक्ष जहाँ पर इन सभी उपकरणों को रखा जायेगा इत्यादि शामिल है।

b)डिजिटल और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी:- डिजिटल एक इलैक्ट्रोनिक्स पद्धित है, जो 0 से 1 तक की संख्याओं या सूचनाओं को एकत्रित कर प्रदर्शित करने का काम करती है, जबिक सूचना व संचार प्रौद्योगिकी अपने यंत्रों के माध्यम से संख्याओं तथा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक आदमी से दूसरे आदमी तक संगठन तक संख्याओं व सूचनाओं को पहुँचाने का कार्य करती है, जिसमें दूरसंचार के उपकरण, इन्टरनेट कनेंक्टिविटी, मोबाइल आदि शामिल है। ये दोनों घटक नवोन्मेषी सेवाओं, उत्पादों व सेवाओं के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर संचालित करने का कार्य करते हैं। इस दृष्टि से यह डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक अहम घटक है।

c) डिजिटलीकरण का क्षेत्र:- जब ये सभी उपकरण या घटक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वह एक समूह बन जाता है। इसमें वे सभी क्षेत्र या घटक शामिल है, जहाँ देशों की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक स्तर पर डिजिटल उत्पादों, सेवाओं का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। आज कल ये समूह इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि नयी

आर्थिक गतिविधियों या व्यावसाय के नये-नये माँडल हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं, चाहे वह व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर अर्थव्यवस्था के मुख्य कारक जैसे:- मीडिया, वित्तीय क्षेत्र, वाणिज्यिक सेवाऐं, पर्यटन, परिवहन आदि। सभी में डिजिटलीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है।

d) वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्था की सीमा व प्रभाव को मापने के लिये इन घटकों का अनेक प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और इस कार्य हेतु आई. टी. (IT) क्षेत्रों के उपयोग पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन (OECD, 2017) तथा पहला व्यापार एवं विकास का एक संयुक्त राष्ट्र संघ (UNCTAD, 2017) के अनुसार - "डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में आई टी क्षेत्र के अन्तर्गत निवेश तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों एवं विकास से जुड़े मुद्दों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि रोजगार एवं आई टी के सक्षम क्षेत्रों का पर्याप्त विकास हो सके।"14,-15

इस प्रकार कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश एवं विकास नीतियों को दिशा प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं, श्रमिकों व फर्मी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, के संबंध में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अहम कारक है।

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्थाः- भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की शुरूआत सन 1990-91 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री पी. व्ही. नरसिंहराव सरकार द्वारा संचालित किया गया, आर्थिक सुधार कार्यक्रम (वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण) से मानी जाती है। इसके तहत सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बैकिंग क्षेत्र ने अपने ग्राहकों की नगद लेनदेन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये ए.टी.एम. (ATM) जैसी मशीनों की प्रक्रिया शुभारंभ की थी। तब से भारत ने डिजिटल क्षेत्र में धीरे-धीरे विकास प्रक्रिया को जारी रखा और 2010 तक पहुँचने के बाद डिजिटल क्षेत्र में विस्फोट किया था, जो आज भी जारी है।

भारत ने अपनी डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के तहत न केवल आर्थिक दृष्टि से वित्तीय या पूँजी (मुद्रा) क्षेत्र को शामिल किया है, बल्कि ई-कॉमर्स, ई-गर्वनेस, विनिर्माण, इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्र, उपभोक्ता बाजार व इन्टरनेट का सर्वाधिक उपयोग करने वाले लोगों को भी शामिल किया है। देश में दिन-प्रतिदिन लोगों (इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं) की बढ़ती हुई संख्या इस बात की ओर इशारा करती है कि विश्व में यह देश सर्वाधिक इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं के उच्चतम प्रतिशत वाले देशों में से एक बन गया है। भारतीय सूचना व संचार प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि - "वर्तमान में भारत अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष 200 मिलयन डॉलर का आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है। वर्ष 2017-18 में इसका कुल मूल्य भारत के सकल

घरेलू उत्पाद का 8% था, जिसमें अन्य कार्यों के साथ-साथ व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन भी शामिल था।"16 वर्तमानकालीन सरकार द्वारा न्यू इंडिया मिशन के तहत भारत का शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें बैंक ने उल्लेख किया है कि - ''भारतीय (लोग) प्रतिदिन लगभग 67 बिलियन डॉलर के करीब 100 मिलियन लेनदेन करते है. जो कि वर्ष 2016 की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है।"¹⁷ इन आँकडो से यह साबित होता है कि किस प्रकार भारत सरकार तथा नागरिक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यही कारण है कि लोगों की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 का पूरा बजट देश के डिजिटलाईजेशन की प्रक्रिया के लिये समर्पित कर दिया है। उनके अनुसार (निर्मला सीतारमण) - ''डिजिटलीकरण की प्रक्रिया न केवल ऐसे लोगों, जिन्हें सरल, तेज व सुरक्षित लेनदेन करने का मौका मिलता है, के लिये आवश्यक है, बल्कि सम्पूर्ण वित्तीय प्रवाह की प्रक्रिया के लिये भी जरूरी है,''¹⁸ ताकि तीव्रगति से लोगों के नगद लेनदेन संबंधी कार्य पूर्ण होने के साथ-साथ बैकों का पैसा बैकों में ही जमा रहे, क्योंकि इसी संचित पूँजी के सहयोग से ही सरकार अपने विकास कार्यो को गति प्रदान करती है और लोगों के लिये एक संरचनात्मक ढाँचा का निर्माण करने में सक्षम होती है।

ई-कॉमर्स (वाणिज्य), जिसे वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के मामलें में डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक अहम अंग माना जाता है, देश में काफी तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यह एक ऐसा अंश है, जिसे वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री हेतु आदेश प्रदान करने के लिये कम्प्यूटर आधारित नेटवर्क का सहारा लिया जाता है, लेकिन इन वस्तुओं व सेवाओं और उनकी कीमतों का भुगतान ऑनलाईन नहीं किया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संघ के अनुसार - ''ई-कॉमर्स के अन्तर्गत वस्तुओं व सेवाओं का लेनदेन किसी एक व्यक्ति, घरों, उद्यमों, सरकारों और अन्य सभी निजी संगठनों के बीच हो सकता है।''¹⁹ यह इन सेवाओं या वस्तुओं को ग्राहकों तक भेजने का कार्य ही नहीं करता बल्कि एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय तक उत्पाद व सेवाऐं बेचने का भी कार्य करता है। आज देश में इस क्षेत्र ने इतनी अधिक प्रगति अर्जित कर ली है कि देश में ई-कॉमर्स बाजार बढकर 35 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।20

हालाँकि देश में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने कोविड-19 महामारी की अवस्था में गति पकड़ी है। इस महामारी ने नवाचारों से लेकर व्यक्तियों के व्यवहारों में इस प्रकार का बदलाब उत्पन्न किया है कि अधिकांश लोग डिजिटल प्रक्रिया को अपना रहे हैं। केन्द्रीय आई टी एवं इलैक्ट्रोनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी का मानना है कि - "भले ही कोविड-19 महामारी ने मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया हो, परन्तु इसके कारण देश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे- इलैक्ट्रोनिक्स, विनिर्माण, इंजीनियरिंग, आदि में डिजिटल रूप से जो बदलाव उत्पन्न किये है, उसकी बजह से देश डिजिटल अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन डालर तक पहुच सकती है।"²¹

64

भारत में जिस गित से डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रचार-प्रसार हो रहा है, उसके लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में से संचालित किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिये एक काल्पनिक हाइवे, जो कि इन्टरनेट के माध्यम से संचालित होगा, का निर्माण किया गया और व्यक्तियों से लेकर सरकारी कामकाज को ई-गर्वनेस की प्रक्रिया के माध्यम से करने की बात की गयी थी। इससे देश का प्रत्येक नागरिक घर बैठे इन्टरनेट के माध्यम से कोई भी सरकारी काम व उससे संबंधित सूचना आसानी से प्राप्त कर सकता है।

भारत उपभोक्ताओं की दृष्टि से डिजिटल क्षेत्र में विश्व के उक्त सभी देशों की तुलना में सबसे अग्रणी रहा है। वर्ष 2018 में कुल 560 मिलियन भारतीय लोगों ने इन्टरनेट का उपयोग किया था, जो कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश माना जा रहा है।22 इसका कारण देश की बढ़ती हुई आबादी में डिजिटल क्षेत्र के प्रति बढती हुई जागरूकता है, जिसमें सरकार का भी अहम योगदान (डिजिटल इंडिया कार्यक्रम) रहा है, क्योंकि इन्टरनेट की पहुँच को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की मुख्य भूमिका रही है। यही ऐसे कारण है कि वर्तमान अर्थात वर्ष 2021 में भी भारत दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में डिजिटल अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे आगे है। आँकडे बताते हैं कि वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में लगभग 82.5 मिलियन भारतीय उपभोक्ताओं ने इन्टरनेट का उपयोग किया है, जो कि वर्ष की शुरूआत में इसकी संख्या केवल 79.18 मिलियन थी अर्थात देश में यह अनुमानित वृद्धि 3.8% रही है।23

भारत न केवल इन्टरनेट के उपयोग में अग्रणी रहा है, बल्कि डिजिटल उत्पादों एवं सेवाओं के क्षेत्र में भी सबसे आगे है। एक वेबसाईट (इनवेस्ट इंडिया डॉट गर्वमेन्ट डॉट इन) के अनुसार - "भारत ने वर्ष 2020 में सम्पूर्ण दुनिया की तुलना में कुल 2018 बिलियन ऐप डाउनलोड किये थे, जो कि कुल वैश्विक उपयोग का लगभग 14% है।"²⁴ इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे आगे और सबसे अग्रणी डिजिटल बाजार के रूप में उभरकर आया है, जो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक है।

सोशल मीडिया, जिसे एक देश के सूचना तंत्र के क्षेत्र में अहम माना जाता है, ने भी डिजिटल अर्थव्यवस्था के

क्षेत्र में अपनी मुख्य भूमिका अदा की है। आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत का सोशल मीडिया क्षेत्र औसत रूप से डिजिटल मंच पर हर हफ्ते कुल 17 घण्टे बिताता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन जैसे देशों में संलग्न सोशल मीडिया से कही अधिक है।²⁵

भारत को डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश कराने में निजी संगठनों या व्यावसायिक उद्यमों के साथ-साथ सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र की भी मुख्य भूमिका रही है। भारत सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी पहचान दिलाने के लिये राष्ट्रीय बायोमैट्कि डिजिटल पहचान कार्यक्रम आरंभ किया था, जिसके तहत कुल 1.2 बिलियन से अधिक भारतीय लोगों को एक डिजिटल पहचान प्रदान की है।26 यह भारत सरकार का सबसे बडा डिजिटल आधार पहचान कार्यक्रम है, जिसमें 12 अंकों की संख्या दर्ज है, जो लोगों को उनकी आँखों की रोशनी, उंगलियों के निसान, तस्वीर, नाम, जन्म तिथि, उम्र, लिंग तथा पता आदि को दर्ज करने के बाद एक विशिष्ट आधार पहचान प्रदान करती है।²⁷ इसका सबसे बड़ा फायदा लोगों को वित्तीय क्षेत्र में मिला है, क्योंकि इस विशिष्ट आधार पहचान संख्या के माध्यम से लोगों के बैंक में स्थित खातों के साथ जोड़ दिया गया है। आधार कार्ड को लोगों के बैंक खातों से जोडने की पहल में वर्ष 2014 में 56 मिलियन, वर्ष 2017 में 399 मिलियन और वर्ष 2018 में कुल 870 मिलियन भारतीय लोगों को उनके बैंक खातों से जोड़ दिया गया है,28 जबिक निजी क्षेत्रों में देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में पहचान दिलाने में रिलायंस कंपंनी का सबसे बडा इन्टरनेट नेटवर्क, जिसका नाम ''जियो'' है, ने भारतीय लोगों को कुछ समय के लिये मुफ्त इन्टरनेट स्मार्टफोन सेवा प्रदान करके अपनी मुख्य भूमिका अदा की है और अधिक से अधिक लोगों को इन्टरनेट का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया है। इसके अलावा इन्टरनेट क्षेत्र का सबसे बड़ा इन्टरनेट सर्च इंजन गूगल (Google) ने वर्ष 2020 में भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटल जेशन फण्ड के लिये कुल 10 बिलियन डॉलर की धनराशि की घोषणा की है,²⁹ ताकि देश में तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास हो सके और अधिक से अधिक लोग इन्टरनेट का उपयोग कर सके।

विश्व के 17 ऐसे विकसित देशों, जो डिजिटल या इन्टरनेट का उपयोग करने के क्षेत्र में अग्रणी है, का सर्वेक्षण किया गया, जिसका मूल्यांकन करने के बाद एक बात चौकाने वाली दृष्टिगोचर हुई और वह यह थी कि इन सब देशों की तुलना में भारत के नागरिक सबसे अधिक इन्टरनेट का उपयोग करते पाये गये थे। भारत में लोगों द्वारा जो सर्वाधिक संख्या में इन्टरनेट का उपयोग किया जा रहा है, उसके कारण है-इन्टरनेट कनैक्टिविटी की लागत, डिजिटल नींव की उचित व्यवस्था, मोबाईल उपकरणों की पर्याप्त संख्या तथा उसकी घटती लागत, इन्टरनेट की तीव्र गित एवं विश्वसनीयता डिजिटल खपत देश, ब्लागिंग एवं सूक्ष्म ब्लोगिंग, डिजिटल चैटिंग पर्याप्त मात्रा में डिजिटल ऐपों की डाउनलोडिंग करना आदि दृष्टिकोण से देश में लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परन्तू यहाँ यह ध्यान देना अति-आवश्यक है कि भारत में यह

वृद्धि (इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं) एक देश अर्थात इण्डोनेशिया के बाद दर्ज हुई है अर्थात भारत इण्डोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2014 से 2017 तक इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में जो 90% की वृद्धि हुई है, वह इण्डोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर दर्ज है।³⁰

भारत में तेजी से जो इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत के अधिकांश लोग डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार है और इस प्रक्रिया में सरकार ने जो पहल की है, वह सराहना के पात्र है, लेकिन इन सब संभावना के बावजूद इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी है, जैसे- देश के संरचनात्मक ढाँचे में बिजली तथा पक्की सड़कों की व्यवस्था, हालाँकि आज काफी हद तक देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें उपलब्ध है तथा बिजली की भी व्यवस्था है, परन्तु फिर भी कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर उक्त दोनों की उपलब्धतता नदारद है, इसीलिये संरचनात्मक ढाँचे में सुधार के बाद ही डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रगति की संभावना उत्पन्न होगी।

भविष्यः- भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य कैसा है ? क्या वह अच्छा होगा या फिर निम्न स्तर पर, आँकड़ो पर दृष्टि डालें तो यह साबित होता है कि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जायेगी तथा इस दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा अग्रणी देश होगा। आइये अब हम आँकड़ो के आधार पर तथा कुछ गैर-सरकारी संगठनों व हमारी सरकार के नेताओं के कथनों के आधार पर देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे।

हमारे देश के अर्थशास्त्रियों तथा नीति निर्माताओं का कहना है कि जब से सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपने पैर पसारने शुरू किये हैं, तब से भारत में भी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आरंभ हो गया और भारतीय नीति-निर्माताओं ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के सतत विकास हेत् वर्ष 2030 तक के लिये कुछ प्रमुख निहितार्थ भी निर्धारित कर दिये हैं, जो देश को डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में आगे ले जाने के लिये महत्वपूर्ण सिद्ध होगे। भारत सरकार की आई.टी. मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार - "भारत ने डिजिटल क्रांति में प्रवेश किया है, इसलिये वह (भारत) वर्ष 2025 तक 1 ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन जायेगा।"³¹ मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हम डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु मैकिन्से (एक डिजिटल अर्थव्यवस्था सलाहकार फर्म) के साथ साझेदारी कर रहे है तथा इसके विकास हेतु सतत रूप से सम्पर्क में है, परन्तु मैकिन्से का कहना है कि हम इस क्षेत्र में या 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था तभी बन पायेगे, जब हम देश के कुछ क्षेत्रों जैसे - कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, विनिर्माण तथा परिवहन आदि क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की प्रक्रियाओं को लागू करे, अभी हम कुछ क्षेत्रों में (सोशल मीडिया, व्यापार-व्यवसाय, उपभोक्ता बाजार) में ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य के संकट में एक और डिजिटलीकरण सलाहकार फर्म रेडशीर (त्मकेममत) ने कहा है कि-"भारत वर्ष 2030 तक ऑनलाईन खुदरा बाजार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाईन बाजार होगा, जिसका वार्षिक सकल व्यापारिक मूल्य 350 बिलियन डॉलर का होगा।"³²

इस प्रकार उक्त आँकड़ो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में भारत का भविष्य उच्च स्तर पर है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हमारा देश सम्पूर्ण विश्व में डिजिटल अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शीर्ष स्तर पर होगा।

निष्कर्षः- डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसे मानव के लिये अपने कार्यों हेतु (सामाजिक-आर्थिक) सबसे सरल व आसान, तीव्र गित से, समय की बचत आदि संदर्भ में देखा जाता है, आज के समय की एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बन गयी है। पिछले 2 वर्षों में (कोविड-19) इस अर्थव्यवस्था ने भारतीयों से लेकर सरकार तक के लिये उल्लेखनीय योगदान दिया है और अधिक से अधिक भारतीय लोग भी डिजिटलीकरण प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि आज सम्पूर्ण विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, यदि इसी प्रकार से यह अर्थव्यवस्था संचालित रही तो इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटलीकरण रूप से सबसे शीर्ष स्तर पर होगी।

संदर्भ :

- Digital Economy:-Definition, Advantages, Disadvantages. (https://www.topper.com)
- Sharma ,Radhika and Sharma ,Karishma (07 October 2021) "Harnessing India's Digital Economy :- Private Sector Championing the cause of Digitalization. (www.investindia.gov.in), 07 October 2021.
- 3. Ibid
- Maiti, Moinak and Kayal, Parthajit (2017) Digitization:-Its Impact on Economic development and Trade. The Journal of AEFR.
- Khan, Saima, Khan, Dr. Shazia and Aftab, Mohsina (2015)
 Digitization and its Impact on Economy. International Journal of Digital Library Services.
- 6. Shukla, Dr. Mansi and Bose, Ms. Shilpi (2017). Impact of Digitalization in Economy and the effects of Demonetization. ELK Asia Pacific Journal.
- What is Digital Economy? Difination from Whatis.com_searchCIO.
 - (https://searchcio.techtarget.com) By:- Mary K Partt
- Ramija, B (2018) "Indian Digital Economy Opportunities and Challenge, International Journal of Current Resarch, Vol. 10, Issue 10, pp. 77338-74344, October 2018.

 Barefoot, K, Curtis D, Jolliff W, Nicholson JR and Omohundro R (2018) Defining and measuring the digital economy. Working paper. Bureau of Economic Analysis, United States Department of Commerce, Washington, DC. Available at: https://www.bea.gov/system/files/papers/wp2018-4.pdf

- 10. Brynjolfsson E and Kahin, B, eds(2002) Understanding the Digital economy massachusetts institute of Technology, Cambridge, MA.
- 11. D.S. Evans, "The antitrust economics of multi-sided platforms markets", Yale Journal on Regulation, Vol. 20, PP 325-382, 2003.
- 12. World bank (2016) World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington, DC.
- 13. Brennen S and Kreiss D (2014) Digitalization and Digitazation. Culture Digitally, 8. Available at: https://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitazation.
- 14. OECD (2017) OECD Digital Economy Outlook 2017. OECD Publishing, Paris.
- 15. UNCTAD (2017). information Economy Report 2017:-Digitalization, Trade and Development. (United Nations Publication, Sales No. Sales No. E. 17.11.D.8, New York and Geneva)
- 16. Digital economy a \$ 1 trillion opportunity for India (https://www.thehindubusinessline.com) Feb. 20, 2019.
- 17. Indian Digital Economy in 2020, "Times of Malta" (www.timesof malta.com) 1 Feb. 2020.
- 18. Ibid
- OECD (2011), OECD Guide to measuring the Information Society 2011, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264113541-en.
- 20. To see reference Number (16)
- 21. India can become \$ 1 Trillion digital economy in 5 year:-Mosfor it, "The Economic Times" (News Paper) 07 October 2021.
- Noshir, K, Madgavkar, A, Kshirsagar, A and Gupta, R (27 March 2019) Digital India:- Technology to transform a connected nation. (www.mckinsey.com) 27 March 2019.
- 23. Sharma, R and Sharma, K (07 October 2021) "Harnessing India's Digital Economy:- Private Sector Championing the cause of Digitalization (www.investindia.gov.in) 07 October 2021.
- 24. Ibid
- 25. We are social, Digital in 2018:- Southern Asia, January 2018.
- 26. Unique Identification Authority of India, April 2018.
- 27. About Aadhar, Unique Identification Authority of India, uidai.gov.in
- 28. UIDAI, Id insight.
- 29. To see the reference Number (23)
- 30. To see the reference Number (22)
- 31. To see the reference Number (16)
- 32. Neha Alawadhi (1 July 2021) India's Consumer digital economy to grow 10x to \$ 800 bn by 2030:- Redseer. (www.business-standard.com) 1 July 2021